PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Tuesday, 30th November 2010, Page: 10
Width: 16.85 cms Height: 13.42 cms, Ref: pmin.2010-11-30.49.47

एड्स के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से छल

प्रसंग

प्रमोद भार्गव

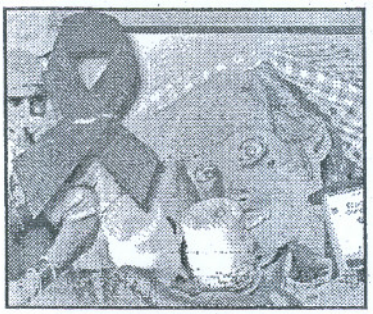

एड्स की दवा बनाने वाली कम्पनियां अब एड्स के नये मरीजों तलाश में गैर सरकारी संगठनों के जरिये ग्रामीण महिलाओं में 'एड्स के विषाणु' खोजने में लग गयी हैं जिससे इस जानलेवा रोग के बहाने करोड़ों रुपये की दवाओं की खपत सरकारी महकमों में की जा सकें। ताजा अध्ययनों में हरियाणा में 1,219 ग्रामीण महिलाएं एड्स से पीड़ित बतायी गयी हैं। ये आंकड़े एड्स कंट्रोल सोसायटी ने जारी किये हैं। सोसायटी ने आगाह किया है कि ये आंकड़े केवल शहरी और कस्बाई अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से इकट्ठे किये गये हैं। यदि सुदूर ग्रामों में सर्वे किया जाय तो आंकड़े भयावह हो सकते हैं। हैरानी की बात है कि ये सभी महिलाएं गरीब होने के साथ गंदी बस्तियों से जुड़ी हैं। सर्वे में एच.आई.वी. पॉजिटिव से जुड़ी हाईप्रोफाइल की एक भी महिला एड्स पीड़ित नहीं दर्शायी गयी हैं। इससे जाहिर होता है कि ये आंकड़े एकपक्षीय होने के साथ केवल दवा कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उछाले गये हैं। आंध्र प्रदेश सरकार तों एड्स रोगियों के लिए पेंशन तक दिये जाने का अदूरदर्शी फैसला लेने की सोच रही है। इधर लखनऊ के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एड्स की ऐसी अचूक दवा बना लेने का दावा किया है जिसे एड्स उपचार की गारंटी माना जा रहा है। ऐसे में एड्स को हौवा बनाकर सर्वेक्षणों के द्वारा इसके नये रोगी क्यों तलाशे जा रहे हैं?

हमारे देश में एड्स फैलने की जिस तरह से भयावह तस्वीर पेश की जा रही है, वह बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों का सुनियोजित षड्यंत्र व देश के आम, गरीब व लाचार नागरिकों से किया जा रहा छल है। और हम हैं कि इसे इस हद तक स्वीकारते चले जा रहे हैं कि हाल ही में आंध्र-प्रदेश सरकार ने एड्स के मुफ्त इलाज की सुविधा लेने वाले रोगियों को पेंशन देने तक का अदूरदर्शी फैसला ले लिया है। एड्स रोगियों को पेंशन देने की शुरुआत के साथ ही उत्तरोत्तर पूरे

देश में एड्स मरीजों की संख्या में आश्चर्यजनक ढंग से इजाफा शुरू हो जाएगा। क्योंकि एड्स का खतरनाक हौवा खड़ा करने वाली जो देशी-विदेशी आर्थिक अनुदान प्राप्त समाज सेवी संस्थाएं हैं, वे एड्स दवा निर्माता कम्पनियों की कठपुतली हैं। उनकी रोजी-रोटी, स्वाबलम्वन और आत्मनिर्भरता इन्हीं कम्पनियों की अनुकम्पा और अनुदान पर टिकी है। निकम्मे व निठल्ले चरित्र के लोग भी पेंशन के लालच में खुद को एड्स रोगी घोषित कराने से गुरेज नहीं करेंगे। चूंकि एड्स रोगी की पहचान गुप्त रखने की शर्त भी जुड़ी है इसलिए सामाजिक लांछन, प्रताड़ना व बहिष्कार से भी ये लोग बचे रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलवाला है, इसलिए रिश्वत लेकर चिकित्सकों को इच्छुक व्यक्ति को एड्स रोगी घोषित करने में भी कोई परहेज नहीं होगा। अव्वल तो यह जरूरी नहीं है कि एचआईवी पॉजिटिव प्रत्येक व्यक्ति एड्स का मरीज हो? एड्स व टीबी की दवाएं लेकर वह लम्बे समय तक एकदम स्वस्थ्य रह सकता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियां गैर सरकारी समाजसेवी संगठनों के माध्यम से एड्स का इतना खतरनाक हौवा खड़ा करती हैं कि दवा कम्पनियों को अपने व्यावसायिक हित साधने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही हल्लों के नतीजतन आंध्र प्रदेश सरकार एड्स रोगियों को पेंशन सुविधा देने के लिए मजबूर हुई और कालांतर में इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी होना निश्चित है। क्योंकि अब तक ये दवा कम्पनियां सूचीबद्ध एड्स रोगियों को पकड़कर उसे अपनी दवा खपाती थीं और अब महामारी का तांडव रच सीधे राज्य सरकारों को दवाएं खपाएंगी।

दरअसल एचआईवी ग्रस्त रोगी को ही जानलेवा एड्स का रोगी मान लिया जाता है और उसे चिकित्सक एंटी रिट्रोवाइलर थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। इन दवाओं की पहली खुराक की कीमत आठ हजार के लगभग होती है जो अस्पतालों अथवा एड्स नियंत्रण केन्द्रों से मुफ्त में मिलती है। इन दवाओं के नियमित सेवन से मूल रोग तो बेअसर रहता है लेकिन रोगी की प्रतिरोधात्मक क्षमता का बेतहाशा ह्रास हो जाता है। परिणामस्वरूप दूसरे और तीसरे चरण की खुराकें निश्चित रूप से लेने की सलाह चिकित्सक देते हैं। इन दोनों चरणों की दवाएं रोगी को मुफ्त में देने का प्रावधान अब तक नहीं है लिहाजा मजबूरीवश बेहद महंगी इन दवाओं को रोगियों को खरीदना होता है। और दवा कम्पनियों की बल्ले-बल्ले हो जाती है। करोड़ों-अरबों की दवाएं सरलता से खप जाती हैं। हालांकि लखनऊ के आयुर्वेक चिकित्सक डॉ. संतोष पाण्डेय ने 22 हर्बल पौधों के मिश्रण से तैयार सीरप और एक कैप्सूल के मार्फत 19 महीने में एड्स को जड़ से ठीक करने का दावा किया है। मई 2010 में इन्हें इस दवा का 240422 क्रमांक से पेटेन्ट भी मिल गया है। यह पेटेंट उन्हें करीब 11 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला।

(1 दिसम्बर, विश्व एड्स दिवस के परिप्रेक्ष्य में)